

कॉर्पोरेट गवर्नेंस

प्रलिस के लयः

कॉर्पोरेट गवर्नेंस, केंद्रीय जाँच ब्यूरो, बैंकग वनयऱमन अधनयऱम

मेन्स के लयः

कॉर्पोरेट गवर्नेंस और संबंघतऱ मुददे

चरचा में क्यौं?

चंदा कोचर (ICICI बैंक की पूरव CEO) कॉर्पोरेट जगत में धोखाधड़ी संबंघी खतरे के सचेतक के रूप में शलमलऱ हैं ।

- **केंद्रीय जाँच ब्यूरो (CBI)** ने आरोप लगलया है कऱ ICICI बैंक ने **बैंकग वनयऱमन अधनयऱम**, RBI के दशऱ-नरऱदेशौं और बैंक की करेडऱटऱ नऱतऱ कऱ उल्लंघन करते हुए वेणुगोपाल धूत दवलरऱ प्रवर्ततऱ वीडयऱकौन समूह की कंपनयऱौं को 3,250 करोड़ रुपए कऱ करेडऱटऱ सवीकृत कयऱ थऱ ।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस:

परचयः

- कॉर्पोरेट गवर्नेंस नयऱमौं, प्रथऱओं और प्रकरयऱओं की प्रणऱली को संदरभतऱ करता है, इसके दवलरऱ एक कंपनी को नरऱदेशतऱ और नयऱतऱरतऱ कयऱ जऱतऱ है, जो यह सुनशऱचतऱ करने में महतऱत्वपूरण भूमकऱ नभऱतऱ है कऱ वऱयवसऱय नैतकऱ रूप से तथऱ उनके हतऱधऱरकौं के सरवोत्तम हतऱ में चलऱए जऱते हैं ।
- कॉर्पोरेट गवर्नेंस की प्रमुख ज़मऱमेदऱरयऱौं में से एक कॉर्पोरेट लऱलच को रोकनऱ तथऱ यह सुनशऱचतऱ करनऱ है कऱ वऱयवसऱयौं को उत्तऱरदऱयी और पऱरदरशी तऱरीके से संचऱलतऱ कयऱ जऱए ।
- मज़बूत नैतकऱ मऱनकौं को लऱगू करके तथऱ वऱयक्तयऱौं को उनके कऱर्यौं के लयऱ उत्तऱरदऱयी बनऱकर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस लऱलच को रोकने और शेयरधऱरकौं, गऱरहकौं एवं वऱयऱपक समुदऱय के हतऱौं की रकषऱ करने में मदद कर सकतऱ है ।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सदऱधऱंतः

नषऱपकषतऱ:

- नदऱशक मंडल को शेयरधऱरकौं, करमचऱरयऱौं, वकऱरेतऱओं और समुदऱयौं के सऱथ उचतऱ एवं समऱन वचऱर से वऱयवहऱर करनऱ चऱहयऱ ।

पऱरदरशतऱ:

- बोरुड को वतऱतऱय प्रदरशन, हतऱ संबंघी मतभेद और शेयरधऱरकौं एवं अनऱय हतऱधऱरकौं को ज़ोखमऱ जैसी सथतऱके बऱरे मेंसमय पर सटीक तथऱ स्पष्ट जऱनकऱरी प्रदऱन करनी चऱहयऱ ।

ज़ोखमऱ प्रबंधन:

- बोरुड और प्रबंधन को सभऱ प्रकरऱ के ज़ोखमऱौं कऱ नरऱधऱरण तथऱ उन्हें नयऱतऱरतऱ करनऱ चऱहयऱ । उन्हें प्रबंधतऱ करने के लयऱ संबदध सफऱरशऱौं पर कऱरऱरवऱई करनी चऱहयऱ । उन्हें सभऱ संबंघतऱ पकषौं को ज़ोखमऱौं की मौजूदगी तथऱ सथतऱके बऱरे में सूचतऱ करनऱ चऱहयऱ ।

ज़मऱमेदऱरी:

- बोरुड कॉर्पोरेट मऱमलौं और प्रबंधन गतवऱधऱयऱौं की नगऱरऱनी के लयऱ ज़मऱमेदऱर है ।
- इसे कंपनी की प्रगतऱ और प्रदरशन के बऱरे में पतऱ हऱना चऱहयऱ, सऱथ ही उसकऱ समरथन करनऱ चऱहयऱ । इसकी ज़मऱमेदऱरी में CEO की भरती और नयऱुकतऱ करनऱ भी शऱलमलऱ है । इसे कऱसी कंपनी एवं उसके नवऱशकौं के सरवोत्तम हतऱ में कऱर्य करनऱ चऱहयऱ ।

जवऱबदेही:

- बोरुड को कंपनी की गतवऱधऱयऱौं के उददेश्य और उसके ऱचरण के परणऱमौं की वऱयऱख्या करनी चऱहयऱ । बोरुड एवं कंपनी कऱ नेतृत्व कंपनी की कषमतऱ एवं प्रदरशन के ऱकलन के लयऱ जवऱबदेह है । इसे शेयरधऱरकौं के महतऱत्व के मुददौं को संपरेषतऱ करनऱ चऱहयऱ ।

भारत में कॉर्पोरेट प्रशासन के संदर्भ में नैतिक मुद्दे:

- **व्यक्तिगत रुचि के बीच मतभेद:**
 - शेयरधारकों की कीमत पर संभावित रूप से व्यक्तिगत रुचि को समृद्ध करने वाले प्रबंधकों की चुनौती एक बड़ी समस्या है **हाल ही की एक घटना में** ICICI बैंक की पूर्व कार्यकारी चंदा कोचर ने अपने पता के लिये एक व्यापार के हिस्से के रूप में वीडियोकॉन कंपनी को ऋण स्वीकृत किया।
- **कमज़ोर बोर्ड:**
 - अनुभव और पृष्ठभूमि की विविधता का अभाव इन बोर्डों की कमज़ोरी का एक प्रमुख वषिय रहा है। शेयरधारकों के व्यापक हितों के मामले में बोर्ड के प्रदर्शन पर सवाल उठते रहे हैं।
- **स्वामित्व और प्रबंधन का पृथक्करण:**
 - परिवार द्वारा संचालित कंपनियों के मामले में भारत की कुछ शीर्ष कंपनियों सहित अधिकांश कंपनियों में स्वामित्व और प्रबंधन को अलग करना एक प्रमुख चुनौती बनी हुई है।
- **स्वतंत्र नदिशक:**
 - स्वतंत्र नदिशक पक्षपातपूर्ण होते हैं और प्रमोटर्स की अनैतिक प्रथाओं की जाँच करने में सक्षम नहीं होते हैं।

संबंधित पहलें

- भारत में कॉर्पोरेट गवर्नेंस पहल की ज़िम्मेदारी कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (Ministry of Corporate Affairs- MCA) एवं **भारतीय प्रतभिति और वनिमिय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India- SEBI)** पर है। उदारीकरण के बाद वर्ष 1990 के दशक में भारत के कॉर्पोरेट क्षेत्र को बड़े बदलावों का सामना करना पड़ा है।
- सेबी खंड 49 के माध्यम से भारत में सूचीबद्ध कंपनियों के कॉर्पोरेट गवर्नेंस की नगिरानी और नयिमन करता है।
- **कंपनी अधिनियम, 2013** बड़े हुए और नए अनुपालन मानदंडों के माध्यम से प्रकटीकरण, रिपोर्टिंग एवं पारदर्शिता को बढ़ाकर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिये औपचारिक संरचना प्रदान करता है।

भारत में कॉर्पोरेट गवर्नेंस में सुधार:

- **विविध बोर्ड बेहतर बोर्ड:**
 - इस संदर्भ में व्यापक 'विविधता' है, जिसमें लिंग, जातीयता, कौशल और अनुभव शामिल हैं।
- **मज़बूत जोखिम प्रबंधन नीतियाँ:**
 - बेहतर नरिणय लेने के लिये प्रभावी और मज़बूत जोखिम प्रबंधन नीतियों को अपनाना क्योंकि यह सभी नगिमों के सामने आने वाले **रसिक-रिविंड ट्रेड-ऑफ** के मामले में गहरी अंतरदृष्टि विकसित करता है।
- **प्रभावी शासन अवसंरचना:**
 - चूँकि अंततः बोर्ड किसी संगठन के सभी कार्यों और नरिणयों के लिये ज़िम्मेदार होता है, इसलिये संगठनात्मक व्यवहार को नरिदेशित करने के लिये वशिषिट नीतियों की आवश्यकता होगी।
 - यह सुनिश्चित करने के लिये **बोर्ड और प्रबंधन के बीच उत्तरदायित्वों को स्पष्ट रूप से नरिधारित किया गया है**, बोर्ड के लिये प्रतनिधिमंडलों के संबंध में नीतियाँ विकसित करना वशिष रूप से महत्त्वपूर्ण है।
- **बोर्ड के प्रदर्शन का मूल्यांकन:**
 - बोर्डों को मूल्यांकन में सामने आई कमज़ोरियों को दूर करके अपनी शासन प्रक्रियाओं में सुधार करना चाहिये।
- **संवाद:**
 - बोर्ड के साथ शेयरधारकों के संवाद को सुगम बनाना महत्त्वपूर्ण है। एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके साथ शेयरधारक किसी भी मुद्दे पर चर्चा कर सकें।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रश्न. सत्यम कांड (2009) के परपिक्ष्य में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये कॉर्पोरेट प्रशासन में लाए गए परविरतनों पर चर्चा कीजिये। (2015)

प्रश्न. 'शासन', 'सुशासन' और 'नैतिक शासन' शब्दों से आप क्या समझते हैं?(2016)

स्रोत: लाइव मटि

